

याद रखें
भगवान देकर
भी परखता है और
लेकर भी।

- अज्ञात

धू-धू करके जलती दिल्ली

साथ उठने-बैठने वाले, धंधा-कारोबार करने वाले लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। राजधानी में उपद्रव शुरू होता है तो फिर चलता ही जाता है, उस पर काबू पाने में पचास घंटे से भी ज्यादा वक्त लग जाता है।

जीवन सिंह।

दिल्ली के कुछ इलाकों में तीन दिन चली सांप्रदायिक हिंसा की लपटें धीरे-धीरे शांत हो रही हैं। इस पागलपन में 24 लोगों की जान जाने की खबर है जबकि घायलों की संख्या सैकड़ों में है। जिस दिल्ली को शंघाई या सिंगापुर बनाने की बात की जाती है, वह दिन-रात किसी लावारिस शहर की तरह धू-धू करके जलती रहती है, लगता ही नहीं कि जिम्मेदार लोगों को इससे कोई परेशानी है।

देश का यह कैसा विकास हम कर रहे हैं? अंततः यह हमें कहां ले जाने वाला है? आखिर कैसा समाज हम बना रहे हैं, जो बिना किसी ठोस वजह के भी भड़क उठता है। साथ उठने-बैठने वाले, धंधा-कारोबार करने वाले लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। राजधानी में उपद्रव शुरू होता है तो फिर चलता ही

जाता है, उस पर काबू पाने में पचास घंटे से भी ज्यादा वक्त लग जाता है। और यह सब जिस समय हो रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर थे। पूरी दुनिया का मीडिया उनके साथ था। दिल्ली की घटनाओं को लेकर जारी ग्लोबल चर्चा आज कोरोना वायरस को भी मात दे रही है तो यह स्वाभाविक है। भारत की राजधानी में ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, फिर देश के बाकी हिस्सों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि एक दलील यह भी बनती है कि प्रशासनिक अमला ट्रंप के दौर को लेकर व्यस्त था, इसलिए इस हादसे से निपटने में वह पूरे दमखम से नहीं लग पाया। यह विडंबना भी कम नहीं कि हिंसा के वक्त कोई राजनीतिक दल हालात सुधारने के

लिए तिनका भी हिलाता नहीं दिखा, लेकिन मामला शांत होते ही हर तरफ से जुबानी तीर चलने लगे। अभी का वक्त दोषी तय करने का नहीं है, हालांकि कुछ नाम जगजाहिर हैं और दिल्ली कोर्ट ने उन पर कोई कार्रवाई न करने को लेकर दिल्ली पुलिस से सवाल भी किया है। अभी की जरूरत शांति को स्थायी बनाने और सभी देश घायलों को अस्पताल पहुंचाने की है।

मृतकों के परिजनों को मुआवजे दिए जाएं और अपना कारोबार खोने वाले हर व्यक्ति के नुकसान की भरपाई की जाए, ताकि लोगों की जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट सके। सबसे जरूरी बात यह कि पूरी दिल्ली, पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा हो। उन्हें अहसास कराए कि वे

अकेले नहीं हैं। कहना गैरजरूरी है कि ऐसे हादसे सिर्फ देसी-विदेशी निवेशकों को नहीं, हर सकारात्मक आर्थिक पक्ष को हतोत्साहित करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। उनकी अपील का मान रखने की पहली जवाबदेही दिल्ली के सरकारी अमले पर आती है। यह विवाद सीएए के विरोध में एक नए धरने और उसके खिलाफ जताए गए एतराज से शुरू हुआ, जिसके अलग-अलग रूप देश के कई इलाकों में देखे जा रहे हैं। दिल्ली को शांत करने के साथ ही केंद्र सरकार को व्यापक संवाद और विचार-विमर्श की एक ऐसी प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए, जिससे इस तरह के टकराव की गुंजाइश कहीं और न बने।

अद्भुत शक्ति

अशोक वोहरा।

मनुष्य का मन यह सब समझने में सक्षम है। जो विशालता हमें बाहर दिखाई देती है वह हमारे अंदर भी उसी तरह है। भगवत गीता के ग्यारहवें अध्याय में पूर्ण

धर्म-दर्शन



ब्रह्मांड को धारण और उसकी क्षमता को समझने का उल्लेख किया गया है। हमारी रूप या सार्वभौमिक रूप से परिचय करवाते हैं, वह उनके इस रूप को देखकर स्तब्ध खड़े रह जाते हैं। हमारी समझ सीमित होती है लेकिन अनुभव से परे जाने की क्षमता हमें मौजूद होती है। जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि जितना हम जानते हैं उस सीमा के बीच में हम जो नहीं जानते उसे भी ग्रहण करने के लिए सक्षम होते हैं। हम धन्य हैं कि मनुष्य के रूप में हमें अद्भुत शक्ति है। आश्चर्य की बात है कि सूक्ष्म जगत के भीतर सार्वभौम है, संपूर्ण संसार-सीमित दायरे के अंदर असीम समाया होता है और भ्रम के अंदर सत्य।

संपादकीय

हिंदी का उत्थान

देश की परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आज हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन हिंदी के उत्थान और विकास के लिए उनके योगदान को भूलाया नहीं जा सकता है। विदेशमंत्री रहते हुए संयुक्तराष्ट्र संघ में 2017 में उन्होंने ने हिंदी में भाषण देकर पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई थी। सुषमा स्वराज अपनी प्रखर भाषण शैली और बेवाक हिंदी के लिए जानीजाती थी। संसद में जब बोलती थीं तो सन्नाटा पसर उठता था। भारत की संसद से लेकर वैश्विक मंच पर उन्होंने हिंदी का मान बढ़ाया। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी प्रेम किसी से छुपा नहीं है। अटल जी अपने विदेशी दौरों के समय कई मंचों पर हिंदी में अपनी बात रखी। 1977 में संयुक्तराष्ट्र संघ में उन्होंने अपना पहला भाषण हिंदी में दिया था। यह बेहद प्रभावशाली भाषण था जो नस्लवाद और मानवधिकारों पर दिया गया था। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू भी हिंदी के विशेष हिमायती थे। उनकी पहल पर ही 14 सितम्बर को 'हिंदी दिवस' रूप में मानाया जाता है। क्योंकि 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को संविधान सभा में अधिकारिक भाषा सम्मान मिला था। सोशलमीडिया में हिंदी का अच्छा प्रयोग हो रहा है। लोगों की पहली पसंद बने ट्विटर पर भी हिंदी पर काफी ट्वीट किए जा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसे जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल सका है। अब वक्त आ गया है जब हमें हिंदी की वैश्विक स्वीकार्यता को समझते हुए राजनीति को किनारे रख हिंदी को और संवृद्ध बनाने के लिए काम करना चाहिए।

लेकिन ट्रंप और मोदी ने लाखों की भीड़ को हिंदी यानी नमस्ते से संबोधित किया। अपनी भारत यात्रा के दौरान ट्रंप ने तीन बार हिंदी में ट्वीट किया।

हिंदी हुई ग्लोबल थैंक्स ट्रंप!

प्रभुनाथ शुक्ल।

भारत और अमेरिकी संबंधों में गुजरात का मोटेरा स्टेडियम नई इबादत लिखेगा। राष्ट्रपति बनने के बाद अपनी पहली यात्रा पर भारत आए दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्सियत डॉनल्ड ट्रंप बेहद खुश और गौरवान्वित दिखे। लेकिन एक बात जो खुल कर सामने आई है वह है हिंदी की अहमियत को लेकर। मोदी और ट्रंप की इस जुगलबंदी ने हिंदी का ग्लोबल मान बढ़ाया है। वैसे तो मोटेरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम की मूल थीम हिंदी यानी नमस्ते ट्रंप पर आधारित थी। लेकिन ट्रंप और मोदी ने लाखों की भीड़ को हिंदी यानी नमस्ते से संबोधित किया। अपनी भारत यात्रा के दौरान ट्रंप ने तीन बार हिंदी में ट्वीट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हिंदी की स्वीकार्यता को निश्चित रूप से बढ़ाया है, यह हर भारतीय और हिंदी प्रेमी के लिए गौरव की बात है। ट्रंप ने हिंदी फिल्म शोले और शाहरुख का भी जिक्र किया। जबकि देश में हिंदी भाषा की स्वीकार्यता पर संसद से लेकर सड़क तक खूब राजनीति होती है। पूर्वोत्तर भारत में हिंदी और हिंदी भाषियों के साथ क्या सलूक होता है यह बात किसी से छुपी नहीं है। दक्षिण भारत में हिंदी को लेकर क्या स्थिति है सब जानते हैं। गुजरात में



हिंदी भाषियों पर किस तरह जानलेवा हमले हुए यह कहने की बात नहीं है। लेकिन ट्रंप ने उसी गुजरात की धरती से हिंदी को बड़ा सम्मान दिया है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा भले मिल गया हो लेकिन राष्ट्रभाषा का सम्मान आज तक नहीं मिल पाया है। सरकारी परीक्षाओं को हिंदी माध्यम से कराने पर भी राजनीति होती है। अंग्रेजी सोच की हिमायती राजनीति हिंदी बोलने में अपना अपमान और शर्म महसूस करती है। अधिकांश राजनेता अपने ट्यूट अंग्रेजी में करते हैं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान और हिंदी की अहमियत समझते हुए अपनी भारत यात्रा को

हिंदीमय बना दिया। इससे यह साबित होता है कि हिंदी अब बेचारी नहीं बल्कि ग्लोबल धमक वाली हो गई है।

अंग्रेजी के हिमायत यह कह सकते हैं कि ट्रंप ने यह सब अमेरिका में होने वाले आम चुनाव के लिए किया। क्योंकि अमेरिका में भारतीय मूल के 40 लाख लोग रहते हैं। लेकिन आलोचकों को यह सोचना होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को हिंदी में ट्वीट की क्या जरूरत थी। वह अपनी बात अंग्रेजी में भी कह सकते थे। निश्चित रूप से हिंदी का ग्लोबल मान बढ़ाने में ट्रंप और मोदी का अहम योगदान है। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा हम भारत आने के लिए तत्पर हैं। हम रास्ते में हैं, कुछ ही घंटों में हम सबसे मिलेंगे। दूसरे और तीसरे ट्वीट में उन्होंने भारत और अमेरिकी संबंधों का जिक्र किया। इसका असर भी अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों पर बेहद गहरा होगा। लोग इस ट्वीट के राजनीति मायने चाहे जो निकालें, लेकिन एक बात सच है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। हिंदी में संबोधन किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की कोई नई पहल नहीं है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब 2010 में भारत आए तो उन्होंने भी अपने सत्कार से प्रभावित होकर हिंदी में 'बहुत-बहुत धन्यवाद' बोलकर भारत और भारतीयता के प्रति अभार जताया था। जबकि भाषण का अंतिम संबोधन 'जयहिंद' से किया था।

अष्टयोग-4961					
1	2	4	6		
21	1	36	39		
3	4		1	2	
36	30	26			
5	6	1	2	4	
48	6	32	22		
		4	2	1	

प्रस्तुत खेल सुटोक् व बोर्ड को पद्धति का मिश्रण है, खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं, पहले काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगा, सौधो अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक हीना अनिवार्य हैं।

अपना ब्लॉग सरकार एक कॉर्पोरेशन को बेच डाले

मोहन। एलआईसी की मुख्य शक्ति उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। आज इसके पास 12 लाख एजेंट और 5000 डिजिटलप्लेट अफसर हैं, जो मार्केटिंग के बेहतर तौर-तरीके अपनाते हैं। उनकी कोशिशों से एलआईसी के पास आज 42 करोड़ पॉलिसी धारक हैं, जिनमें से 30 करोड़ ने व्यक्तिगत पॉलिसियां ले रखी हैं और बाकी ने ग्रुप इंश्योरेंस ली है। जाहिर है, इन पॉलिसी होल्डरों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सरकार पॉलिसी अवधि के बीच में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बदल सकती है! वित्त मंत्रालय के अफसरों ने फिलहाल यह कह कर जवाब टाल दिया है कि आईपीओ अगले वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में ही लाया जाएगा। वैसे यह एक अनैतिक कदम होगा कि मात्र 5 प्रतिशत कानूनी हिस्सेदारी से सरकार एक कॉर्पोरेशन को बेच डाले। यह कॉर्पोरेशन प्रति माह अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट अपने रेगुलेटर आईआरडीए (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) को देता है, जो बाद में संसद में पेश की जाती है।

